



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-21022020-216307  
CG-DL-E-21022020-216307

असाधारण  
EXTRAORDINARY  
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)  
प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 728]  
No. 728]

नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 21, 2020/ फाल्गुन 2, 1941  
NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 21, 2020/ PHALGUNA 2, 1941

गृह मंत्रालय  
अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 फरवरी, 2020

का.आ. 797(अ).—विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) की धारा 5 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार यह निर्धारित करने के लिए कि क्या हन्नीवट्टेप नेशनल लिबेरेशन काउंसिल (एच एन एल सी) को विधिविरुद्ध संघ घोषित करने के पर्याप्त कारण हैं अथवा नहीं, एतद्वारा, मेघालय उच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश, माननीय न्यायमूर्ति श्री एच. एस. थेंगखियू की अध्यक्षता में “विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिकरण” का गठन करती है।

इस बारे में दिनांक 13 दिसम्बर, 2019 की पहली अधिसूचना सं. का. आ. 4454 (अ) रद्द कर दी गई है।

[फा. सं. 11011/02/2019-एनई-V]

सत्येन्द्र गर्ग, संयुक्त सचिव

**MINISTRY OF HOME AFFAIRS****NOTIFICATION**

New Delhi the 21st February, 2020

**S.O. 797(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967), the Central Government hereby constitutes “The Unlawful Activities (Prevention) Tribunal” consisting of Shri Justice H.S. Thangkhiew, Senior Judge of Meghalaya High Court, for the purpose of adjudicating whether or not there is sufficient cause for declaring the Hynniewtre National Liberation Council (HNLC) of Meghalaya as unlawful association.

Earlier Notification No. 4454 (E), dated 13<sup>th</sup> December, 2019, issued in this regard, stands cancelled.

[F. No.11011/02/2019-NE-V]

SATYENDRA GARG, Jt. Secy.